



**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR**

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE G. S. AHLUWALIA

ON THE 19th OF SEPTEMBER, 2024

WRIT PETITION No. 13162 of 2024

JAHGEER SINGH

Versus

***SACHIV PANCHAYAT EVAM GRAMIN VIKAS MANTRALAYA AND
OTHERS***

Appearance:

Shri Krishan Kumar Gautam – Advocate for the petitioner.

***Shri Mohan Sausarkar – Government Advocate for the
respondents/State.***

ORDER

This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking following reliefs:

- “(अ) यह कि याचिकाकर्ता का प्रकरण/याचिका जो कि मेंडमस “परमादेश” के अंतर्गत है जिसके तहत याचिकाकर्ता मान्नीय उच्च न्यायालय से इस याचिका के माध्यम से निर्देश चाहती है।
- (ब) यह कि ऑनलाईन दर्ज सामग्री खरीद ब्यौरा दिनांक 14.03.2024 के अनुसार अनावेदक क्रं0 06, 07, 08 के द्वारा अन्य दोषी अधिकारियों से साठ-गाठ करके 1320104 रुपये का फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि का गबन कर लिया गया है जिसमें न्यायहित में कार्यवाही आवश्यक है।
- (स) यह कि अनावेदक क्रं0 06 के विरुद्ध चार लाख चौअन हजार पाच सौ निन्यानवे रुपये का आरोप दिनांक 29.01.2024 के अनुसार प्रमाणित है ऐसी स्थिति में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत उपधारा की कंडिका 5 के अंतर्गत अनावेदक क्रं0 06 को निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत भाग लेने के सम्बंध में 6 वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करने के सम्बंध में निदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।



- (द) यह कि अनावेदक क्रं0 06 के विरुद्ध धोखाधड़ी व दस्तावेज की कूट रचना एवं शासकीय राशि का गबन प्रमाणित है तब अनावेदक क्रं0 07 को पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत सरपंच पद से पृथक करने के सम्बंध में तथा कार्यवाही लम्बित होने के दशा में अनावेदक क्रं007 अपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न है।
- (ड) यह कि याचिकाकर्ता व अन्य द्वारा लगातार किये गये आवेदनों के आधार पर अनावेदक क्रं006, 07, 08 के विरुद्ध धोखाधड़ी कर शासकीय राशि के गबन करने के सम्बंध में एफ.आई.आर. हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।”

2. By order dated 28.05.2024, this Court had directed the petitioner to produce the certified copy of order sheets of the Court of Prescribed Authority-cum-Chief Executive Officer, Jila Panchayat Dindori in respect of application filed under Section 40 Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhinyam.

3. The petitioner has filed I.A. No.8867/2024 to show that he had filed an application under Right to Information Act for supply of the order sheets. However, it has been informed that the case has not been registered.

4. It is not the case of petitioner that although the application under Section 40 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhinyam was filed but the same has not been registered.

5. Be that whatever it may be.

6. Since there is a serious dispute as to whether petitioner has filed an application under Section 40 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhinyam or not, therefore, this petition is **dismissed** with liberty to petitioner that if so advised, then the petitioner



may file a fresh application under Section 40 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam.

(G.S. AHLUWALIA)
JUDGE

SR*